DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 31 मई 2022

'जलाशयों को अतिक्रमण से बचाएं, रिवाइव करने के लिए काम करें'

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे यहां मौजूद सभी जलाशयों के संरक्षण और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए सतर्कता से काम करें। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की डिविजन बेंच ने यह आदेश राहुल डबास नाम के एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

याचिका में लगाया गया आरोप- अथॉरिटीज की उपेक्षा के शिकार हैं तालाब और जोहड़

याचिकाकर्ता ने लाढपुर में 12 बीघे और

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश

18 बीघे में फैले दो जलाशयों (जोहड़/तालाब) पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और कोर्ट में आरोप लगाया कि ये जलाशयों के तौर पर रखरखाव के लिए संबंधित प्राधिकारियों की उपेक्षा के शिकार हैं। खासतौर पर डीडीए को कटघरे में खड़ते हुए याचिकाकर्ता ने एडवोकेट आनंद यादव के जरिए कोर्ट में दावा किया कि इन्हें जबकि जलाशय के तौर पर मान्यता हासिल है।

वकील ने संबंधित जगहों की कई तस्वीरें कोर्ट के सामने रखीं। उन्हें देखने के बाद बेंच ने कहा कि तस्वीरें देखने से ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता जिससे वहां पर जलाशय होने का आभास हो। हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जलाशयों पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण न हो और जहां मिले, वहां से उसे तत्काल हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जलाशयों को बचाने के लिए फेंसिंग और उनकी लगातार निगरानी जैसे सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

ओपन जिम पर चोरों की नजर, टूटे ढांचों से लोग हो रहे जख्मी

■ शमसे आलम, रोहिणी

रोहिणी के कई पार्कों से धीरे-धीरे ओपन जिम के इक्विपमेंट गायब होते जा रहे हैं। कई जर्जर हालत में पड़े हैं। लोगों का कहना है कि रखरखाव के अभाव में जिम इक्विपमेंट टूट रहे हैं, जिसे चोर लेकर फरार हो जाते हैं। इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

सेक्टर-6: परशुराम पार्क में लगे ओपन जिम के इक्विपमेंट टूट रहे हैं। उन्हें असामाजिक तत्व चोरी कर ले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ओपन जिम के रखरखाव को लेकर कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में एक्विपमेंट लगातार गायब होते जा रहे हैं। कई टूटे पड़े हैं। टूटे पार्ट्स के साथ एक्सरसाइज करना भी खतरनाक है।

सेक्टर-19: डिस्ट्रिक्ट पार्क में लगे ओपन जिम के कई पार्ट्स अलग हो गए हैं। कई चोरी हो गए है। इसे लेकर स्थानीय

रोहिणी के पार्कों से गायब हुए ओपन जिम के उपकरण

■ पार्कों में एक्सरसाइज करना हो गया खतरनाक

लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि समय रहते हुए अगर खराब पार्ट्स की मरम्मत कराई जाए। जिम परिसर की सतह भी उखड़ रही है। ऐसे में जिम करना भी सेफ नहीं है।

सेक्टर-21: पॉकेट 7 के महिला पार्क में ओपन जिम के इक्विपमेंट भी मेंटिनेंस के अभाव में बदहाल हो गए हैं। कई पार्ट्स अलग-अलग हो गए हैं तो कई चोरी हो गए हैं। अब यह ओपन जिम सिर्फ नाम का जिम रह गया है। कोई भी अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जिम के साथ लगे इंस्ट्रक्शन बोर्ड तक को चोर ले गए।

सेक्टर-22: जीडी गोयंका स्कूल के पीछे डीडीए पार्क में भी करीब 3 साल पहले ओपन जिम लगाया गया था। तीन साल बीत जाने के बाद भी सुध लेने कोई नहीं आया। आरोप है कि जिन कर्मचारियों पर जिम ठीक करने की जिम्मेदारी है, जब उन्हें फोन करते हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कई उपकरण टूटे हैं, जिनकी मरम्मत जरूरी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 31 मई, 2022

नियमों पर खरे नहीं उतरे डीडीए के फ्लैट

वर्ष 2019 से अब तक पांच योजनाओं में से कोई भी रेरा से पंजीकृत नहीं

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैट दिल्लीवासियों को तो लुभाने में नाकाम हो रही रहे हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के नियमों पर भी खरे नहीं उतर रहे। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद डीडीए का कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा से पंजीकृत नहीं हो पाया है। हालांकि डीडीए की कोशिशें जारी हैं। रेरा दिल्ली में अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट को पंजीकृत करवाने की प्रक्रिया डीडीए ने वर्ष 2019 में शुरू की थी। इसके बाद से अब तक डीडीए पांच हाउसिंग योजनाएं ला चुका है, लेकिन इनमें से कोई योजना रेरा में पंजीकृत नहीं हो सकी। नियमानुसार सभी बिल्डरों और सरकारी एजेंसियों को अपने रिहायशी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रेरा को देनी होती है और उसमें पंजीकरण भी करवाना होता है।

डीडीए के एक दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट रेरा के पास अभी भी हैं पंजीकरण के लिए लंबित, खरीदारों को लुभाने में नाकाम

बताया जाता है कि इस समय भी डीडीए के एक दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट रेरा के पास पंजीकरण के लिए लंबित हैं। पिछले साल 20 दिसंबर को हुई एक सुनवाई में डीडीए के 14 लंबित मामलों के आवेदन को रेरा ने अस्वीकृत भी कर दिया था। हालांकि, अधिकारियों का कहना था कि डीडीए सरकारी एजेंसी है और इसके सभी प्रोजेक्ट में अपना ही पैसा लगा होता है। पंजीकरण की अनिवार्यता वहां होनी चाहिए, जहां बिल्डर फ्लैट बुक करके अग्रिम पैसा लेते हैं। हालांकि, रेरा इस तर्क से सहमत नहीं हुआ।

पंजीकरण में गतिरोध

बताया जाता है कि डीडीए की ओर से लागत की सही जानकारी नहीं दी गई। कुछ प्रोजेक्ट में स्वीकृत प्लान नहीं है। इंश्योरेंस पालिसी को लेकर भी डीडीए ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, वहीं कुछ फाइलों में पैन कार्ड की डिटेल नहीं है। डीडीए ने एक मई, 2016 से चल रहे प्रोजेक्ट और शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी भी नहीं दी। निर्माण पूरा होने को लेकर भी डीडीए ने फार्म ए और फार्म बी में अलग-अलग जानकारी दी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी ----------DATED 31/05/2022

फेरबदल | एनडीएमसी के सचिव बने विक्रम सिंह मलिक, दिल्ली जल बोर्ड के नए सीईओ बने पी. कृष्णमूर्ति, नई दिल्ली के डीएम बने संतोष कुमार राय

दिल्ली में बदले गए 34 आईएएस समेत 40 अधिकारी

निहारिका राय

गरिमा गुप्ता

के महेश

अंकुर गर्ग

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली में सोमवार को हुए एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के दौरान 40 सीनियर आईएएस व दानिक्स अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। ट्रांसफर किए गए इन अधिकारियों में 34 आईएएस हैं, जबकि 6 दानिक्स सेवा के अफसर हैं। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर से ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। उधर, दिल्ली के नए उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना के कार्यभार संभालने के बाद अचानक इतने बड़े पैमाने पर आईएएस और दानिक्स अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को काफी अहम माना जा रहा है। जारी आदेश के तहत 1995 बैच के आईएएस अधिकारी एच राजेश प्रसाद को शिक्षा विभाग से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग लगाया गया है। 1997 बैच के के पी. कृष्णमूर्ति को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) का सीईओ नियुक्त किया गया है। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय को विशेष सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2009 बैच के आईएएस के महेश को डूसिब का सीईओ बनाया गया है। वहीं 2010 के आईएएस कुलानंद को स्पेशल सेक्रेट्री (फाइनेंस) बनाया गया है। वहीं उन्हें स्पेशल सेक्रेट्री का अतिरिक्त पदभार दिया गया है।

एसडीएम हुए इधर-उधर... नई दिल्ली जिला का डीएम आईएएस संतोष कुमार राय को बनाया गया है। आईएएस मोनिका प्रियदर्शनी साउथ दिल्ली के डीएम होंगी। वहीं साउथ जिला की डीएम रही आईएएस सोनालिका जिवानी को अर्बन डवलपमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं आईएएस सोनिका सिंह सेंट्रल दिल्ली का डीएम होंगी। साउथ-वेस्ट के डीएम के रूप में 2013 बैच के आईएएस हेमंत कुमार संभालेंगे। वहीं साउथ-वेस्ट के डीएम रहे विक्रम सिंह मलिक एनडीएमसी का सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं ईशा खोसला अब साउथ-ईस्ट की डीएम होंगी। ईस्ट जिले के डीएम का पद 1997 बैच के आईएएस अनिल बांका लेंगे। साउथ-ईस्ट के डीएम रहे 2001 बैच के आईएएस विश्वेंद्र सोशल वेलफेयर का स्पेशल डायरेक्टर का पद संभालेंगे।

तारिक थॉमस बने डीडीए कमिश्नर... 2011 बैच के आईएएस तारिक थॉमस को डीडी का कमिश्नर बनाया गया है। 2010 बैच के आईएएस राम निवास शर्मा को श्रम आयुक्त आयुक्त का पद संभालेंगे। वहीं आईएएस प्रिंस धवन को स्पेशल सेक्रेटरी आईटी बनाया गया है। 1995 बैच के दानिक्स अधिकारी जितेंद्र कुमार जैन को सेवा विभाग में जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं दानिक्स अधिकारी राजेश गोयल, रंजीत सिंह को सेवा विभाग में जिम्मेदारी दी जाएगी। आईएएस अधिकारी अंजलि सहरावत, एंजल भाटी चौहान, वंदना को एमसीडी का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। 1996 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी आशीष कुंद्रा को प्रधान सचिव सह परिवहन आयुक्त बनाया गया है। आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को शिक्षा सचिव बनाया है। डीएसएसबी का चेयरमैन शूरबीर सिंह को बनाया गया है। वहीं तेज तर्रार आईएएस अधिकारी अंकुर गर्ग को आईटी सचिव बनाया गया है। एसबी दीपक कुमार को व्यापार व कर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। नवीन एस.एल. को डीजेबी का सदस्य बनाया गया है। आईएएस खिल्ली राम मीणा को राजस्व विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। सुधीर कुमार को विजिलेंस सचिव सह निदेशक बनाया गया है। संजय गोयल को सचिव, शहरी विकास की जिम्मेदारी दी गई है। 2004 बैच की आईएएस गरिमा गुप्ता को समाज कल्याण सचिव का पद दिया गया है। सुनील कुमार सिंह को डूसिब का सदस्य बनाया गया है। वहीं चोखा राम गर्ग को सूचना एवं प्रसार सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। निहारिका राय को वित्त सचिव, संजीव कुमार मित्तल को एमडी, डीएसआईआईडीसी की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस संजय गिहार को स्वास्थ्य प्रधान सचिव बनाया गया है। आईएएस कृष्ण कुमार को महिला एवं बाल विकास निदेशक और एस.के. जैन को कैट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है।

राष्ट्रीय सहारा

जल स्रोतों का अतिक्रमण न होना सुनिश्चित करे डीडीए : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजधानी के सभी जल स्रोतों की समुचित निगरानी हो व उनपर अतिक्रमण न होने पाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने डीडीए से जल स्रोतों को सुरक्षा को लेकर सभी उचित कदम उठाने को कहा है और अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा उसे बचाने का पूरा प्रयास करने एवं उसकी घेराबंदी भी करने को कहा है। वहां से मलबा व अन्य कचरा को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिससे जल स्रोत पुनर्जीवित रहे। पीठ ने डीडीए से जल स्रोतों का फोटो एक हफ्ते में खींचने एवं

कोर्ट ने डीडीए से जल स्रोतों का फोटो एक हफ्ते में खींचने एवं वहां से सभी अतिक्रमणों को एक महीने के भीतर हटा देने को कहा

वहां से सभी अतिक्रमण को एक महीने के भीतर हटा देने को कहा है, क्योंकि मानसून जून के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली है। इसको लेकर दोनों स्थिति की फोटो भी पेश करने को कहा है।

पीठ ने इसके साथ ही जल स्रोतों के वर्तमान स्थिति एवं वहां से अतिक्रमण या उसको मरम्मत करने के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर देने को कहा है। इस बाबत उसका फोटो भी पेश करने को कहा है। पीठ ने इस मामले की सुनवाई 25 नवम्बर के लिए स्थगित कर दी है।

पीठ ने यह निर्देश राहुल डबास की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है, जिसमें दिल्ली के 12 बीघा व 18 बीघा के दो तालाबों पर अतिक्रमण होने की बात कही गई है। उसने इस बाबत दोनों का फोटो भी पेश कियां जिसमें लग रहा था कि उनकी हालत बदहाल है। फोटो देखने के बाद कोर्ट ने यह माना कि दोनों तालाबों की स्थिति जल स्रोत की तरह नहीं है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 31 MAY, 2022

----------DATED----------

40 OFFICERS TRANSFERRED

Bureaucratic rejig

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Days after the national Capital got a new Lieutenant Governor in Vinai Kumar Saxena, the Delhi government on Monday effected a major bureaucratic reshuffle involving 40 officers. The transfer orders were issued by the Services Department, which comes under the L-G.

Former Principal Secretary (Revenue) and Divisional Commissioner Sanjeev Khirwar, who was shunted out to Ladakh last week following media reports suggesting misuse of official position, has been replaced by 1993 batch IAS officer Khilli Ram Meena.

Earlier, Meena was holding the post of principal secretary cum director, Vigilance.

Many district magistrates have also been transferred.

Monica Priyadarshini, a 2014 batch IAS officer, who was DM of New Delhi district has been transferred to South district. Santosh Kumar Rai has been appointed as the new DM of New Delhi district.

Sonalika Jiwani, who was serving as DM (South) has been posted as special secretary, Urban Development.

Vishwendra, currently posted as DM (Southeast), has been given the additional charge of special director, Social Welfare. Sonika Singh, who was DM (East) and holding the additional charge of DM (Central), has been deputed as DM (Central).

Vikram Singh Malik, posted as DM (South West), has been transferred to the New Delhi Municipal Council (NDMC) as its secretary. Hemant Kumar, a 2013 IAS officer, will assume the charge of DM (South West). Isha Khosla, who was serving as secretary, NDMC, has been posted as DM (South East), while Anil Banka has been posted as DM (East).

Tariq Thomas, a 2011 IAS officer, has been posted as Delhi Development Authority (DDA) commissioner.

Delhi Jal Board CEO Udit Prakash Rai, who was also holding the additional charge of special secretary, Health and Family Welfare, has been posted as special secretary, Health and Family Welfare. P Krishnamurthy, who was chairman Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB), will be replacing Rai as DJB CEO.

Ankur Garg, a 2003 IAS officer, who was posted as commissioner, Trade and Tax, has been transferred as secretary, IT. He will be replaced by S B Deepak Kumar.

Delhi Urban Shelter Improvement Board CEO Garima Gupta has been posted as secretary, Social Welfare and given the additional charge of Women and Child Development secretary and MD of Shahjahanabad Redevelopment Council. K Mahesh, a 2009 batch IAS officer, will replace her at the DUSIB. H Rajesh Prasad, a 1995 batch IAS officer, has been posted as principal secretary of the Public Works Department.

The Municipal Corporation of Delhi, which was recently unified, has received many young officers in its fold. Anjali Sehrawat, a 2013 batch IAS officer, Angel Bhati and Vandana Rao, both 2014 batch IAS officers, have been posted as deputy commissioners in the MCD.

THE HINDU DELHI
TUESDAY, MAY 31, 2022

DDA reopens window for its land pooling scheme till August 25

Says it is the 'last chance' for landowners to form consortiums

STAFF REPORTER
NEW DELHI

In yet another effort to revive interest in its Land Pooling Policy (LPP), the Delhi Development Authority (DDA) on Monday announced reopening of its application window for the scheme for a period of 90 days.

The move to extend the application window till August 25 comes nearly a week after the urban body issued conditional notices for the formation of consortiums in three high-priority sectors – Sector 10-A (in Zone-N), and Sectors 2 and 3 (in Zone-P-II) – where 70% participation of landowners has been achieved.

The DDA, in its public notice, said its latest window for LPP is the "last chance" for the remaining landowners in the three sectors to become a part of the formation of consortiums.

"If the three sectors achieve minimum contiguity and the remaining landowners decide to participate at a later stage; then they will get only 55% of the land in return," said a senior DDA official.

According to the LPP, apart from a minimum participation rate of 70%, contiguous land of 70% is mandatory for the formation of landowners' consortium in a sector.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS the pioneer TED----------

NEW DELHI | TUESDAY | MAY 31, 2022

Major bureaucratic reshuffle in Delhi

40 officers transferred on LG's order

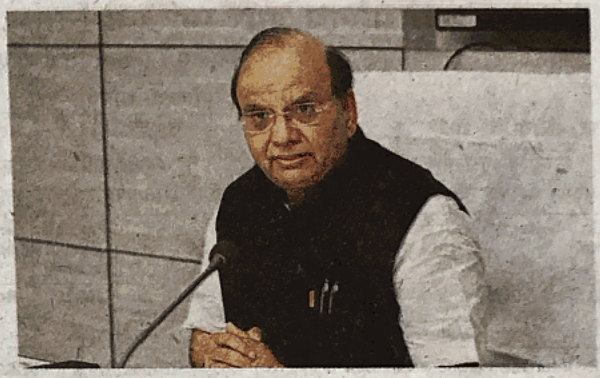

STAFF REPORTER ■ NEW DELH

Days after the national Capital got a new Lieutenant-Governor, Vinai Kumar Saxena, the Delhi Government on Monday effected a major bureaucratic reshuffle involving 40 officers.

Former Principal Secretary (Revenue) and Divisional Commissioner Sanjeev Khirwar, who was shunted out to Ladakh last week following media reports suggesting misuse of official position, has been replaced by 1993 batch IAS officer Khilli Ram Meena. Earlier, Meena was holding the post of Principal Secretary-cum-Director, Vigilance.

The transfer orders were issued by Services Department, which comes under L-G. Many District Magistrates (DMs) have also been transferred.

Delhi Jal Board (DJB) CEO Udit Prakash Rai, who was also holding additional charge of Special Secretary, Health and Family Welfare, has been posted as Special Secretary, Health and Family Welfare.

P Krishnamurthy, who was Chairman, Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB), will be replacing Rai as DJB CEO. Ankur Garg, a 2003 IAS officer, who was posted as Commissioner, Trade and Tax, has been transferred as Secretary, IT.

He will be replaced by SB Deepak Kumar. Monika Priyadarshini, a 2014 batch IAS officer, who was DM of New Delhi district is transferred to South district.

Santosh Kumar Rai has been appointed as the new DM of New Delhi district. Sonalika Jiwani, who was serving as DM (South) has been posted as Special Secretary, Urban Development.

Vishwendra, currently posted as DM (Southeast), has been given the additional charge of Special Director, Social Welfare. Sonika Singh, who was DM (East) and holding the additional charge of DM (Central), has been deputed as DM (Central).

Vikram Singh Malik, posted as DM (South West), has been transferred to the New Delhi Municipal Council (NDMC) as its Secretary. Hemant Kumar, a 2013 IAS officer, will assume the charge of DM (South West).

Isha Khosla, who was serving as Secretary, NDMC, has been posted as DM (South East), while Anil Banka has been posted as DM (East). Tariq Thomas, a 2011 IAS officer, has been posted as Delhi Development Authority (DDA) Commissioner.

Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) CEO Garima Gupta has been posted as Secretary, Social Welfare and given the additional charge of Women and Child Development Secretary and MD of Shahjahanabad Redevelopment Council. K Mahesh, a 2009 batch IAS officer, will replace her at the DUSIB. H Rajesh Prasad, a 1995 batch IAS officer, has been posted as Principal Secretary of the Public Works Department.

The Municipal Corporation of Delhi, which was recently unified, has received many young officers in its fold. Anjali Sehrawat, a 2013 batch IAS officer, Angel Bhati and Vandana Rao, both 2014 batch IAS officers, have been posted as Deputy Commissioners in the MCD.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED-- 31/05/2022

उपराज्यपाल ने 34 आईएएस और छह दानिक्स अधिकारी बदले

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने एक साथ बड़ी पैमाने पर 34आईएएस 6 दानिक्श सहित 40 अधिकारियों का तुंरत प्रभाव से ट्रांसफर कर किया है। इसमें से चार आईएएस और दो दानिक्श अधिकारी राजस्व विभाग में तैनात हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि पब्लिक के शिकायत पर वेंडर के विरूद्ध कार्रवाई करने के बजाय शिकायत को रफा-दफा कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल कार्यालय में मुख्य सचिव कार्यालयों में एकत्र शिकायतों को देखते हुए उनके सुझाव पर विभागों में पारदर्शिता कायम करने के लिए तुंरत प्रभाव से अधिकारियों को पद से इधर-उधर ट्रांसफर कर दिया। डिप्टी सेक्रेट्री अमिताभ जोशी के द्वारा जारी इस आदेश को तुंरत प्रभाव से लागू होगा। शेष | पेज 06 पर

इन अधिकारियों का जारी हुआ है ट्रांसफर...

आइएएस संतोष कुमार को डीएम न्यू दिल्ली, आईएएस मोनिका प्रियदर्शनी (डीएम न्यू दिल्ली)को डीएम साउथ के साथ एडिशनल चार्ज एनयूएलएम, आईएएस सोनालिका जिवानी डीएम साउथ व डीसी हेडक्वार्टर को स्पेशल सेक्रेटरी अर्बन डेभलेपमेंट, दानिक्श सोनालिका सिंह डीएम ईष्ट होल्डिंग चार्ज को डीएम सेंट्रल डिस्ट्रिक, आईएएस हेमंत कुमार को डीएम साउथ वेस्ट, आईएएस विक्रम सिंह मलिक को डीएम साउथ वेस्ट को सेक्रेट्री एनडीएमसी, आईएएस ईशा खोसला को सेक्रेट्री एनडीएमसी को डीएम साउथ ईस्ट, दानिक्श अनिल बंका स्पेशल कमिश्नर टी एंड टी को डीएम ईष्ट, दानिक्श विश्वेंदर को स्पेशल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, आईएएस तारक थॉमस को कमिश्नर डीडीए, आईएएस राम निवास शर्मा एडिशन कमिश्नर एमसीडी को कमिश्नर लेबर इन जीएनसीटीडी, आईएएस प्रिंस धवन एमसीडी से स्पेशल सेक्रेटरी जीएनसीटीडी, दानिक्श जितेंद्र कुमार जैन एमसीडी से जीएनसीटीडी, दानिक्श राजेश गोयल को एमसीडी से जीएनसीटीडी, दानिक्श रंजीत सिंह एमसीडी से जीएनसीटीडी, आईएएस अंजली सहरावत डिप्टी कमिश्नर एमसीडी, आईएएस वंदना राव डिप्टी कमिश्नर एमसीडी, आईएएस आशीष कुंद्रा को वर्तमान पोस्ट के साथ डेवलेपमेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी आई एंड एफसी, आईएएस एच राजेश प्रसाद एजुकेशन से पीडब्ल्यूडी, आईएएस अशोक कुमार सेक्रेटरी एजुकेशन, आईएएस उदित प्रकाश सीईओ जल बोर्ड स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, आईएएस पी कृष्णमूर्ति चेयरमैन डीएसएसएसबी सीईओ दिल्ली जल बोर्ड, आईएएस शूरवीर सिंह डीएसएसएसबी, आईएएस अंकुर गर्ग, ट्रेड टैक्स से सेक्रेटरी आइटी, आईएएस एसबी दीपक कुमार सेक्रेटरी सर्विसेस से कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्स, आईएएस नवीन एसएल सेक्रेटरी सर्विसेस को मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन जल बोर्ड, आईएएस खिलजी राम मीणा राजस्व सचिव, आईएएस सुधीर कुमार सेक्रेटरी कम डायरेक्टर विजिलेंस, आईएएस संजय गोयल नार्थ एमसीडी से अर्बन डेवलेपमेंट, आईएएस गरिमा गुप्ता सीईओ डूसिव से स्पेशल सेक्रेटरी वेल फेयर, आईएएस सुनील कुमार सिंह मेंबर डूसीब, आईएएस चोखा राम गर्ग सेक्रेटरी इनफ्रामेंशन एंड पब्लिसीटी, आईएएस निहारिका राय सेक्रेट्री यूडी से सेक्रेटरी फाइनेंस, आईएएस संजीव कुमार मित्तल को एमडी डीएसआईआईडीसी, आईएएस संजीव गिहार को स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, आईएएस कृष्णन कुमार डायरेक्टर डब्ल्यूसीडी, आईएएस एसके जैन ट्रेड एंड टैक्स से प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैट्स व स्पेशल सेक्रेट्री हेल्थ का अतिरिक्त प्रभार, आईएएस कुमार महेश सीईओ डूसीब, आईएएस कुलानंद जोशी को स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस व स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेस की अतिरिक्त प्रभार दी गई है।

अमर उजाला

जल स्रोत पर अतिक्रमण न हो, निगरानी रखें : हाईकोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजधानी के किसी भी जल स्रोतों पर अतिक्रमण न हो। अधिकारी उन पर अतिक्रमण नहीं होने को लेकर सतत निगरानी रखें।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने डीडीए से जल स्रोतों की सुरक्षा को लेकर सभी उचित कदम उठाने के लिए कहा है और अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उसे बचाने का पूरा प्रयास करने एवं उसकी घेराबंदी करने व वहां से मलबा और अन्य कचरा को हटाने का निर्देश दिया है, जिससे जल स्रोत पुनर्जीवित रहे।

पीठ ने डीडीए से जल स्रोतों की फोटो एक हफ्ते में खिंचने और वहां से सभी अतिक्रमण को एक महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि मानसून जून के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाला है। पीठ ने डीडीए को दोनों स्थिति की फोटो भी पेश करने के लिए कहा है।

पीठ ने इसके साथ ही जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति एवं वहां से अतिक्रमण या उसको मरम्मत करने के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर देने को कहा है।

ये है मामला : पीठ ने यह निर्देश राहुल डबास की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है, जिसमें दिल्ली के 12 बीघा व 18 बीघा के दो तालाबों पर अतिक्रमण होने का आरोप लगाया है। याची ने इस बाबत दोनों का फोटो भी पेश किया, जिसमें लग रहा था कि उनकी हालत बदहाल है।। फोटो देखने के बाद कोर्ट ने यह माना कि दोनों तालाबों की स्थिति जल स्रोत की तरह नहीं हैं।